2006

लोक प्रशासन प्रश्नपत्र-॥

PUBLIC ADMINISTRATION

Paper-II

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 200

Time allowed: Three Hours]

[Maximum Marks: 200

नोट :

- (i) अभ्यर्थी प्रश्न संख्या 1 तथा 5 करें जो अनिवार्य हैं। शेष **तीन** प्रश्न, खण्ड '**अ**' तथा '**ब**' से कम से कम **एक** प्रश्न चुनते हुए करें।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note:

- (i) The Candidate should attempt Question Nos. 1 and 5 which are compulsory. Remaining three questions they should attempt by selecting at least one question each from Section 'A' & 'B'.
- (ii) All questions carry equal marks.

खण्ड – अ SECTION – A

- 1. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए जो 300 शब्दों से अधिक न हों :
 - (क) 'स्थानीय स्वशासन प्रजातन्त्र का आधार है।'' व्याख्या कीजिए।
 - (ख) "संसद की लोक-लेखा सिमिति संघीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था की वास्तविक संरक्षिका है ।" टिप्पणी कीजिये ।
 - (ग) "भारत में विकास प्रशासन में जनता की सहभागिता एक अयथार्थ / मिथक मात्र है ।" विवेचना कीजिए ।

Write notes on any two of the following in not more than 300 words each:

- (a) "Local Self Government is the foundation of democracy." Discuss.
- (b) "Public Accounts Committee of the Parliament is the real watch dog of the finances of the Union Government." Comment.
- (c) People's participation in development administration in India is largely a myth." Discuss.
- 2. लोक वित्त व्यय पर नियन्त्रण करने के कौन-कौन से भिन्न तरीके हैं ? क्या वे तरीके प्रभावशाली हैं ? इन तरीकों को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए ।

What are different methods of exercising control over public finance expenditure? Are these methods effective? Give your suggestions to make these methods more effective.

- 3. भारत में प्रशासन के विरुद्ध लोगों की शिकायतों/नाराजिंगयों का निपटारा कैसे किया जाता है ? भारत में ओमबुड्ज्मैन तरह की संस्थाएँ इन शिकायतों/नाराजिंगयों को निपटाने में किस हद तक कामयाब हैं ? समझाइये । How grievances of citizens against administration are redressed in India ? How far Ombudsman type of institutions are successful in the redressal of citizens grievances in India ? Explain.
- 4. भारत में नवीन आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सार्वजिनक उद्यमों के भविष्य पर एक समीक्षात्मक निबन्ध लिखिए। Write a critical essay on the future of public enterprises in the context of new economic policies in India.

खण्ड – ब SECTION – B

- 5. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर टिप्पणियाँ लिखिए जिनमें प्रत्येक 300 शब्दों से अधिक न हो :
 - (क) "कौटिल्य ने भारतीय प्रशासन की उत्पत्ति को एक आकार दिया।"
 - (ख) "सचिवालय संगठन करदाताओं पर एक भार है, नीति निष्पादन की असफलता के प्रति इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है और यह भारत में वास्तविकता से परे प्रशासन का एक प्रतीक है ।"
 - (ग) ''जिलाधीश/कलेक्टर अधिकाधिक बहु-आयामी बन गया है ।''

Write notes on any two of the following in not more than 300 words each:

- (a) "Kautilya shaped evolution of Indian Administration."
- (b) "Secretariat organization is a burden on the tax payers, lacks accountability for failure of policy execution, and is a symbol of ivory tower administration in India."
- (c) "District Collector has increasingly become multi-dimensional."
- 6. 'ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकायों के गठन और कार्य पद्धित पर 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के प्रभाव' पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखें ।

Write a critical essay on the 'impact of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts on the organization and working of rural and urban local bodies'.

- 7. "भारतीय नियोजन प्रक्रिया ने राज्यों पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार को सशक्त किया है।" टिप्पणी कीजिए। "The Planning mechanism in India has strengthened the authority of Central Government over States." Comment.
- 8. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (क) भारतीय संघवाद की प्रकृति ।
 - (ख) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ग्रामीण विकास में भूमिका ।

Write notes on the following:

- (a) Nature of Indian Federalism.
- (b) Role of District Rural Development Agency (DRDA) in Rural Development.

